SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir. Andhra Pradesh is a lower riparian State. A lot of water is going into the sea. I want to know from the hon. Minister, -I want to ask directly, that when they are not in a position to take up these national projects, - how many projects have been fully funded by the Government of India in various States. Is there any possibility of giving money to the Government of Andhra Pradesh for constructing these two projects?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, When these projects will be cleared for implementation, all these things will be considered.

SHRI YADLAPATI VENKAT RAO; MR.Chairman, Sir, very little water is being harnessed in the Godavari. Only 22 per cent of the water harnessed. It is still going waste into the sea. ! would like to request the hon. Minister to reconsider the proposal for taking it up as a national project.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir. we are very much keen to implement it. The moment the differences are ironed out. we will, certainiv, consider it.

जनचातीय क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाओ के लिए धन

*383. **श्री अभय कांत प्रसाद:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई कार्यों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(घ) इन क्षेत्रों में सिंचाई संबंधी विकास कार्य शुरु करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) जनजातीय क्षेत्रों में सिचाई परियोजनाओं के विकास के लिए राज्यवार विशेषता: झारखंड़ को कितनी घनराशि आबंटित की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन चरण सेठी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी, हां। दसवीं पंचवर्षीय योजना में 73 वृहद एवं 114 माध्यम निर्माणाधीन सिंचाई परियोचनाएं हैं जिनसे 16 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। इन 187 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं की चरम सिंचाई क्षमता 11.27 मि. हे. है और नौवीं योजना तक उपार्जित क्षमता 4.13 मिय हे. है।

(घ) संशोधित राष्ट्रीय जल नीति, 2002 के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई का विकास करने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं क्योंकि इस नीति में "जनजातीय लोगों अथवा सामाजिक रुप से कमजोर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे अन्य विशेष रुप से अलाभकारी समूहों के रिहाइशी क्षेत्रों में अथवा उनके लाभ के लिए परियोजनाओं का अन्वेषण एवं तैयारी के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए" का उल्लेख किया गया है।

केन्द्रीय योजना आयोग ने जल क्षेत्र के विकास के लिए व्यवहार्य बिन्दुओं की पहचान की है जिसमें निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसमें जनजातीय क्षेत्रों की परियोजनाएं भी शामिल हैं ।

1.राज्यों द्वारा पांचवीं योजना से पूर्व एवं पांचवीं योजना अवधि तक 30 वृहद परियोजनाओं को पूरा करना।

2. 0.475 मि.हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के फास्ट ट्रैक के अंतर्गत 20 वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं को पूरा करना।

3. सामान्य एआईबीपी परियोजनाओं/स्कीमों के माध्यम से 3 मि. हे. की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करना।

इसके अतिरिक्त, वर्तमान में जनजातीय क्षेत्रों (जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत) को लाभान्वित करने वाले 69 नये परियोजना प्रस्तावों में से 39 परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं, 29 परियोजनाएं जल संसाधन मंत्रालय की सलाहकार समिति द्वारा तकनीकी-आर्थिक रुप में स्वीकार कर ली गई हैं और एक परियोजना निवेश स्वीकृति हेतु योजना तकनीकी-आर्थिक रुप में स्वीकार कर ली गई है और एक परियोजना निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को सिफारिश की गई है।

जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई विकास के लिए निधियों का आवंटन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनके कुल आवंटन से किया जाता है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए झारखंड सरकार के जनजातीय क्षेत्रों की परियोजनाओं सहित सिचाई परियोजनाओं के लिए कुल आवंटन

14,632.74 करोड़ रुपये है जबकि वार्षिक योजना 2002-03 और 2003-04 के लिए स्वीकृत परिव्यय क्रमश: 2652.00 करोड़ रुपये और 2935.85 करोड़ रुपये है।

Funds for irrigation Projects in Tribal Areas

†*383. SHRI ABHAY KANT PRASAD: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the irrigation works in tribal areas;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, the reasons thereof;

(d) the steps taken by Government to start irrigation related development work in these areas; and

(e) the amount allocated, State-wise, particularly to Jharkhand for development of irrigation projects in the tribal areas?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI ARJUN CHARAN SETHI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

Be Answered on 19.08.2003 Regarding Funds for Irrigation Projects in Tribal Areas.

(a) to (c) Yes, Sir. There are 73 major and 114 medium ongoing irrigation projects in the X Five Year Plan which are benefiting tribal areas of 16 States. The ultimate irrigation potential of these 187 major and medium projects is 11.27 mha. and the achievement of potential upto IX Plan is 4.13 mha.

(d) Special efforts have been initiated by the Government for development of irrigation in tribal areas according to the revised National Water Policy, 2002 which stipulates "special efforts should be made to investigate and formulate projects either in, or for the benefit of, areas inhabited by tribal or other specially disadvantaged groups such as socially weak, scheduled castes and scheduled tribes."

† Original notice of the Question was received in Hindi.

The Union Planning Commission has identified actionable points for development Water Sector wherein following targets had been made which also include projects of Tribal areas:

1. To complete 30 major projects of Pre-fifth and Fifth Plan period by the States.
2. To complete 20 major and medium projects under Fast Track of Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) for creation of additional 0.475 mha of irrigation potential.
3. To create an additional 3 mha of irrigation potential through normal AIBP projects/schemes.

Further, at present, out of 69 New project proposals benefiting the tribal areas (Under Tribal Sub Plan) there are 39 projects under different stages of appraisal in Central Water Commission, 29 have been techno-economically accepted by the Advisory Committee of the Ministry of Water Resources and one project has been recommended to Planning Commission for investment clearance.

(e) The allocation of funds for irrigation development in tribal areas is done by the concerned State Governments out of their overall allocation. The overall allocation for the irrigation projects including projects in the tribal areas for State Government of Jharkhand for the X. Five Year Plan is Rs. 14.632.74 crore white the agreed only for the Annual Plans 2002-03 and 2003-04 is Rs. 2652.00 crore and Rs. 2935.85 crore respectively.

श्री अभय कांत प्रसादः सभापति महोदय, मेरा आज का मूल प्रश्न सवपूर्ण में सिंचाइ वय्वस्था को सुवयवस्थित करने के संबंध में है। आज हमारे देश में अधिकांश नहर परियोजनाएं वास्तव में अपनी घोषित क्षमता की मात्र एक तिहाई सिंचाई ही कर पा रही है। अनेक नहर प्रणालियां आधा-अधूरी पड़ी हैं और किसान के खेत तक नहीं पहुंच सकी हैं, इनमें से अधिकांश झारखंड की है। मैं जानना चाहता हूं कि इनके सही रख रखाव और समान सिंचाई जल वितरण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है।

SHRI ARJUN CHARAN SETHI:Sir, number of steps have been taken to complete the on-going projects. As far as Jharkhand is concerned, the work on seven major and seventeen medium projects are going on. The amount that has so far been spent,- at the end of the Ninth Five Year Plan on the major projects, was Rs 1,579.02 crores. Similarly, amount spent

against the seventeen on-going medium irrigation projects was Rs. 483.17 crores. So, every effort is being made to complete these on-going projects so that the water can be made available for irrigation purpose; and increase the agricultural area of not only in the State of Jharkhand but also in other parts of the country.

श्री कृपाल परमार : सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 69 नए प्रोजेक्ट, प्रोपोजल शूरू किए जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनमें से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में कितनी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं और उनके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है?

SHRI ARJUN CHARAN SETHI: Sir, I need a separate notice for this question.

विदेशों की यात्र करने वाले प्रतिनिधिमंडल

*384. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :††**

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनेक सरकारी और गार-सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशों की यात्रा करते हैं;

(ख) यदि हैं, तो 200-2001,-2002 तथा 2002-2003 के दौरान ऐसे कितने-कितने प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशों की यात्रा की थी; और

(ग) इन प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं पर वर्षवार किताना व्यय किया गया था?

वित्त मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है। सदन के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" और श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछे गए मौखिक प्रश्न संख्या-384 के उत्तर में संभव विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सूचना का केन्द्रीय तौर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।

(ग) विदेश यात्रा के लिए निधियों का आबंटन और विदेश यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय के बारे में सूचना संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की विस्तृत अनुदान मांगों, जो कि वार्षिक रुप से सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाती है, में उपलब्ध है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' द्वारा पूछा गया।